झारखंड स्थापना दिवस राज्य के सतत विकास की ठोस रूपरेखा तय करने का अवसर, आत्मचिंतन कर बनायें योजना

उलगुलान 2050 का लक्ष्य पाने के लिए सतत विकास नीति जरूरी

प्रो दीपक कुमार श्रीवास्तव

निदेशक
आइआइएम रांची

राज्य अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है. यह मौका उत्सव मनाने के साथ पिछली उपलब्धियों को गिनाने, भविष्य की दिशा तय करने और सतत विकास की ठोस रूपरेखा तय करने का समय है. देश के अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड की परिस्थितियां अलग हैं. यहां संसाधन की प्रचुरता है, लेकिन विकास के कई नये आयामों को हासिल करना बाकी है. राज्य के विकास के लिए सतत विकास नीति के बारे में सोचना होगा. इससे उलगुलान-2050 के लक्ष्यों को पाने में मदद मिलेगी.

सतत विकास नीति लागू होने से राज्य का आर्थिक विकास होगा. वहीं यह सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने में सहायक होगा. इससे राज्य स्तर पर प्रशासनिक काम-काज में सुव्यवस्थित बदलाव संभव होंगे. विभिन्न विभाग पारदर्शी रूप से अपने लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों को संपादित करेंगे. इससे प्रशासनिक स्तर पर डाटा आधारित रिपोर्ट का संग्रह करना संभव होगा. यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी के 17 लक्ष्य) बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता जैसे विकल्पों पर मजबूती से काम करने में मददगार सिद्ध होगी. उलगुलान@2050 जैसी एक दीर्घकालिक सोच सतत विकास नीति के लिए प्रेरित करती है. इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने वाली एक स्पष्ट नोडल एजेंसी जैसे राज्य योजना आयोग या राज्य विकास बोर्ड की जरूरत है. यह एजेंसी एसडीजी और उलगुलान@2050 के लक्ष्यों को पाने की रूपरेखा तय कर सकती है. **बाकी पेज 19 पर**

अहम बातें

1. दीर्घकालिक और संतुलित विकास के लिए सतत विकास नीति बने
2. राज्य के विभागों में कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर देने की जरूरत है
3. झारखंड की अगले 25 वर्षों की यात्रा (2025-2050) अवसरों से भरी है
4. सतत विकास नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी की होगी जरूरत

डोमेन विशेषज्ञ टीम का गठन हो

डोमेन विशेषज्ञ टीम का गठन करने से सभी विभागों के बीच एकीकृत योजना तंत्र विकसित होगी. इससे अल्पकालिक योजनाएं दीर्घकालिक सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ जायेंगी. सतत विकास नीति से राज्य न केवल नये दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेगा, बल्कि आर्थिक और सतत विकास के लक्ष्यों को भी पाने में सफल होगा. सतत विकास नीति को प्रभावी करने से नीतियों के निर्माण, उनकी निगरानी और मूल्यांकन में पारदर्शिता आयेगी. जिससे राज्य सरकार उलगुलान@2050 के लक्ष्यों के अनुरूप कई क्षेत्रों में ठोस और सकारात्मक पहल कर सकेगी. इसके लिए राज्य के विभिन्न विभागों में कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर देने की जरूरत है. जिससे आधुनिक तकनीक के उपयोग की अभ्यस्तता बढ़ेगी.

Prabhat Khabar_15.11.2025_P. 1